

लंबे समय से नक्सल समस्या से प्रभावित रहे जगरगुंडा में 21 वर्ष बाद खुली बैंक की शाखा

इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया वरुअल शुभारंभ



सुकमा 19 मई (दण्डकारण्य समाचार)लंबे समय से नक्सल समस्या से प्रभावित रहे छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र के लोगों को भी अब बैंकिंग सुविधा का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास से सुकमा के जगरगुंडा में इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा का वरुअल शुभारंभ किया। बैंक की इस शाखा से आसपास के 12 गांव के लगभग 16 हजार ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधा का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने शुभारंभ कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन इस क्षेत्र

के लोगों के लिए ऐतिहासिक है। लंबे समय से यह क्षेत्र नक्सलवाद से प्रभावित रहा है। पिछले डेढ़ वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार में हम बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित करने में कामयाब हुए हैं। यही कारण है कि आज यहां बैंक की नई शाखा खुली है। लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार की सुरक्षा विकास और विश्वास की रणनीतिएं सुरक्षा बलों के लगातार अभियान और केंद्र और राज्य सरकार के दृढ़ संकल्प से बस्तर अंचल के गांव तेजी से नक्सल समस्या से उबर कर विकास की मुख्यधारा में

शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी में सभी ग्राम पंचायत में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने की गारंटी दी गई है, जिस पर अमल करते हुए 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर प्रत्येक विकासखंड की 10.10 ग्राम पंचायतों में 1460 अटल पंचायत डिजिटल सेवा केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। जहां ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है। एक वर्ष में सभी ग्राम पंचायतों में इस सुविधा का विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को सुशासन तिहार की भी विस्तार से जानकारी

दी। श्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान उन्होंने स्वयं डिजिटल सेवा केंद्रों पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। ग्रामीण यहां बैंकिंग सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि जब वे दंतेवाड़ा में कलेक्टर थेएं तब यह इलाका घोर नक्सल प्रभावित था। अंदरूनी इलाके में जाने के पहले सोचना पड़ता था। वर्ष 2004 में इस भवन में स्टेट बैंक की शाखा थीएं जिसे नक्सलियों द्वारा लूटने का प्रयास किया गया था। आज इसी भवन में इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा खुल रही है। यहां से ग्रामीणों को तेंदुपता बोनसएं किसान सम्मान निधि जैसी अनेक योजनाओं की राशि गांव में ही मिलेगी। वित्तमंत्री चौधरी ने बैंक परिसर में कैश काउंटर और शाखा प्रबंधक कार्यालय का निरीक्षण करते हुए बैंक में अपना भी खाता खुलवाया। उनके साथ महिला आयोग की सदस्य दीपिका सोरी ने भी बैंक में अपना खाता खुलवाया। उल्लेखनीय है कि बैंक के साथ ही एटीएम की सुविधा भी ग्रामीणों के लिए उपलब्ध कराई गई है। शुभारंभ कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी वरुअली जुड़े थे।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और प्रभारी मंत्री केदार कश्यप का सुकमा प्रवास

माओवाद मुक्त पंचायत बड़े सेटी में 1.10 करोड़ के विकास कार्य स्वीकृत

- जनप्रतिनिधियों को एलवद पंचायत कार्यक्रम में शामिल होने सहभागिता की अपील
- युवाओं को खेलभावना से जोड़ने एसपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता का होगा आयोजन



सुकमा 19 मई (दण्डकारण्य समाचार) छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने सुकमा जिले के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की बैठक ली और राज्य के प्रथम माओवाद मुक्त पंचायत बड़े सेटी में कुल 1 करोड़ 10 लाख रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने माओवाद से प्रभावित क्षेत्र में शांति और खुशहाली स्थापित करने हेतु सभी जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से मिलकर काम करने का आग्रह किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि माओवाद से मुक्ति के लिए आप सभी की सहभागिता आवश्यक है।

अगर आपके पंचायत में कोई ऐसा भटका हुआ व्यक्ति है तो उसे समझाकर पुनर्वास के लिए प्रेरित करें। पंचायत के माध्यम से पुनर्वास करने वाले व्यक्ति को मुआवजा देने के साथ ही व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ऐसे पुनर्वास किए हुए व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जाएगा और कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। भविष्य में इनके पूर्व के प्रकरण भी माफ किए जाएंगे। ऐसे लोगों को पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से पुनर्वास कराकर मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। बैठक में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पेशा क्षेत्र के तहत आने वाले ग्राम पंचायतों में केवल आदिवासी

ही सरपंच और अध्यक्ष बन सकते हैं। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को रायपुर आने का आमंत्रण देते हुए कहा कि वे राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी लेकर अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री ने माओवाद मुक्त क्षेत्र की दिशा में हो रहे प्रयासों की सराहना करते हुए सभी जनप्रतिनिधियों को एकजुट होकर कार्य करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की माँग पंचायतों को क्रिकेट किट वितरित करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन को सुकमा प्रीमियर लीग ,एसपीएलड्ड के नाम से पंचायतस्तरीय क्रिकेट

प्रतियोगिता का आयोजन करने निर्देशित किया। कार्यक्रम में आईजी पी सुंदरराज कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव, सीईओ जिला पंचायत नम्रता जैन, डीएफओ अक्षय भोंसले, एसपी उमेश गुप्ता राज्य महिला आयोग सदस्य दीपिका सोरी, नगरपालिका अध्यक्ष हंगाराम मरकाम, जिला पंचायत सदस्य कोरसा सन्तु, जनप्रतिनिधि धनीराम बारसे, अरुण सिंह भदोरिया, नूपुर वैदिक, विश्वराज सिंह चौहान, दिलीप पेदी एवं पाषंदगण सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण, कार्यकर्तागण, सर्व समाज जन सहित बड़ी संख्या में नागरिक सहित अन्य उपस्थित रहे।

स्कूली बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हमने किया काम - वित्त मंत्री

- जगरगुंडा में ग्रामीणों की माँग पर सिंचाई सुविधा के लिए जलाशय और मिनी स्टेडियम की घोषणा

सुकमा 19 मई (दण्डकारण्य समाचार) वित्तमंत्री ओपी चौधरी अपने एकदिवसीय प्रवास में जगरगुंडा पहुंचे थे। बैंक के उद्घाटन के पश्चात वे जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित समाधान शिविर में पहुंचे। शिविर में उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनका हाल चाल पूछा। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने वित्तमंत्री ओपी चौधरी को शिविर में प्राप्त आवेदन पत्रों की जानकारी देते हुए निराकरण की स्थिति से अवगत कराया। समाधान शिविर को संबोधित करते हुए वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार आने से हम तेंदुपता 5500 रुपये में खुरेद रहे हैं। पीएम आवास में 1 लाख 20 हजार रुपये की राशि ग्रामीणों को घर बनाने के लिए दी जा रही है। आज से करीब 12.13 साल पहले जब मैं संयुक्त रूप से दंतेवाड़ा जिले का कलेक्टर था तब सुकमा



भी दंतेवाड़ा जिले में आता था तब बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए मैंने एजुकेशन सिटीएं हूँ तो आसमा उड़ते परिंदे लाइवलीहुड कॉलेज की शुरुवात की थी। आज इसके बहुत ही अच्छे और सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इसके माध्यम से हमने बच्चों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने की शुरुवात की। एक समय था जब हम सड़क मार्ग से पालनार तक ही आ सकते थे। उसके बाद हमारी सरकार के निरंतर प्रयासों से आज हम बिना रुके सीधे जगरगुंडा तक पहुंच रहे हैं। मेरा यह सपना था की मैं जगरगुंडा सड़क मार्ग से जाऊँ। आज मेरा सपना साकार

हुआ। आज से 21 साल पहले यहीं के बैंक को नक्सलियों ने लूट लिया था। वर्तमान में हमारी सरकार के बन जाने से पुनः जनता की सुविधा के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना की गई है। अब आपके सारे बैंकिंग कार्य अब जगरगुंडा में ही होंगे। यहाँ पर जलाशय की माँग आई है जिसे हम बजट में शामिल करेंगे और उसमें 2 करोड़ की राशि का प्रावधान करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण भी किया जाएगा। यहाँ एक मिडिल स्कूल निर्माण की माँग प्राप्त हुई है जिसका कार्य भी किया जाएगा। समूचे राज्य के विकास के साथ ही इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारी सरकार

प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री सुगम यातायात योजनांतर्गत यहीं बस चलाने का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना अंतर्गत जहाँ नेटवर्क नहीं है वहाँ नेटवर्क कनेक्शन स्थापित किए जाएंगे। इस क्षेत्र के सभी बच्चे कलेक्टर बनें, एसपी बनें डॉक्टर बनें, इंजीनियर बनें ऐसी मेरी कामना है। और सभी अच्छे नागरिक बनकर देश के, राज्य के और समाज के विकास में अपना योगदान दें। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य दीपिका सोरी, कलेक्टर सुकमा देवेश कुमार ध्रुव, जिला पंचायत सीईओ नम्रता जैन, बैंक के रीजन्ल मैनेजर गौरीशंकर नायक, एसपी उमेश गुप्ता एसडीएम शबाब खान, सीईओ जनपद कोटा नारद कुमार मांझी जिला पंचायत अध्यक्ष दंतेवाड़ा नंदलाल मुड़ामी, भाजपा जिलाध्यक्ष धनीराम बारसे, राज्य महिला आयोग की सदस्य दीपिका सोरी, जिला पंचायत सदस्य कोरसा सन्तु, जनपद अध्यक्ष कोटा कुसुम लता कवासी, जनपद सदस्य जानकी कवासी, विश्वराज सिंह चौहान, नूपुर वैदिक, जनपद सदस्य आरूषि, सुत्रम पंटा, सरपंच नित्या कोसमा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

एनएमडीसी ने दंतेवाड़ा के शंकिनी.डंकिनी नदी संगम पर किया भव्य घाट निर्माण



दंतेवाड़ा 19 मई (दण्डकारण्य समाचार) दंतेवाड़ा को सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए एनएमडीसी लिमिटेड ने शंकिनी और डंकिनी नदियों के पिचिंग संगम स्थल पर आकर्षक घाट और पिचिंग क्षेत्र का निर्माण किया है। यह परियोजना कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर पहल के तहत रु.298 लाख की लागत से पूरी की गई है। इसका असर कई स्तरों पर देखा जा रहा है। पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। आजीविका के टिकाऊ साधन विकसित हो रहे हैं और यह श्रद्धे को अपना देशस्थ और स्वदेश दर्शन जैसे राष्ट्रीय अभियानों के अनुरूप भी है। दंतेवाड़ा में देश के 52 शक्तिपीठों में से एक देवी दंतेधरी के प्राचीन मंदिर स्थित है

जो चैत्र नवरात्रिए शारदीय नवरात्रि पगुन मेला और भव्य दशहरा उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहता है। बावजूद इसके यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से काफी हद तक अनदेखा रहा है। अब नए घाट के निर्माण से न केवल नदी की प्राकृतिक सुंदरता उजागर हुई है बल्कि यह क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक रूप से भी सशक्त हो रहा है। इस विकास की सबसे विशेष बात यह है कि यह स्थानीय आदिवासी समुदायों की जिंदगी में वास्तविक बदलाव ला रहा है। वर्षों से जंगलों पर निर्भर यह समुदाय अब यह देख पा रहा है कि उनके आसपास की जल.संपदाएं पर्यटन और समृद्धि का केंद्र बन सकती हैं। अब जब सैलानियों की संख्या बढ़ रही है, तो इन परिवारों की आजीविका के नए रास्ते खुल रहे हैं। ये समुदाय अब

ईको टूरिज्म से जुड़कर स्थानीय हस्तशिल्प का प्रदर्शन कर पा रहे हैं और पर्यटकों को सेवाएं देकर नियमित आय अर्जित कर रहे हैं। इसके साथ ही जंगल पर निर्भरता कम होने से उनके जीवनयापन के तरीके अधिक टिकाऊ और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार बन रहे हैं। ग्रामीण यात्रिकों सेवा संभाग दंतेवाड़ा के अधिशासी अभियंता राजविवज टंडन ने कहा कि ए एनएमडीसी की सीएसआर पहल के तहत दंतेवाड़ा में बनाए गए रिटेनिंग वाल और घाटों ने इस क्षेत्र को धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया है। साथ ही, रिटेनिंग वाल यह भी सुनिश्चित करता है कि भविष्य में नदी पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। एनएमडीसी की एक अन्य सीएसआर पहल के तहत दंतेवाड़ा के माड़कम कुटमा समाज को टेंट हाउस सामग्री वितरित की गई है जिससे सामुदायिक ढांचे को मजबूती मिली है और स्थानीय सामाजिक.सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षण मिला है। ये सभी प्रयास एनएमडीसी के केवल समुदाय के आसपास नहीं, बल्कि समुदाय के साथ मिलकर विकास के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।

सुशासन तिहार में राजपुर के सुकली बाई को सौंपी गयी खुशियों की चाबी



नारायणपुर 19 मई (दण्डकारण्य समाचार) सुशासन तिहार अंतर्गत ग्राम पंचायत छोटेडोंगर में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। समाधान शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा मांगों एवं शिकायतों से संबंधित आवेदनों का निराकरण किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना.ग्रामीण अंतर्गत ग्राम मड़ोनार के हितग्राही जंगनू ग्राम राजपुर को सुकली बाई ग्राम छोटेडोंगर के रूपई बाई एवं बड़ागांव के मंगनराम को नर्वनिर्मित आवास में विधिवत गृह प्रवेश कराया गया और प्रतीकात्मक आवास की चाँबी सौंपी गई। हितग्राहियों ने बताया कि पूर्व में कच्चे मकान में बसता के दिनों में छत से पानी टपकने हवा.तृष्ण में छत उड़ जाने, जहरीले कीड़े.मकोड़ों का भय रहता था। वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना.ग्रामीण के तहत पक्का आवास एवं पक्की छत बन जाने से इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना.ग्रामीण अंतर्गत पक्का आवास बनने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को धन्यवाद दिया। कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने हितग्राहियों से पहले और अब के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के बारे में जानकारी ली। उन्होंने शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में हितग्राहियों को बताया तथा योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने हितग्राहियों को नर्वनिर्मित आवास के गृह प्रवेश पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। समाधान शिविर में जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, जनपद पंचायत अध्यक्ष पिंकी उसेण्डी, जिला पंचायत सदस्य राकेश उसेण्डी जनपद पंचायत सदस्य सोनसिंह कोराम, यशबत्ती मांझी, क्षेत्र के सभी सरपंचगण, अधिकारीगण सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

सुकमा 19 मई (दण्डकारण्य समाचार) उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कलेक्ट्रेट कार्यालय सुकमा में युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि बस्तर के खूबसूरत घने जंगल में कई सालों से नक्सल विचारधारा को खत्म करने का प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया जा रहा है।

संस्कार आने वाले 31 मार्च 2026 तक इसे खत्म करने के लिए कड़े इंतजाम कर रही है। इसका आभास करेगुड़ा की पहाड़ियों में चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान से होने लगा है। डिटी सीएम ने सुकमा के पत्रकारों के द्वारा खिंची हुई बेहद अच्छी और खुशनुमा तस्वीर साझा

एसे लोग बस्तर संभाग के हर जिले में मौजूद है। हमें चुनौत कराना होगा किसी एक का क्वॉल जहाँ शिक्षा पहुंची तो वहाँ लोग शिक्षित होंगे और उन्हें रोजगार और स्वरोजगार मिलेगा, लेकिन नक्सल विचारधारा के समर्थन से हमें क्या लाभ मिल रहा है। इस पर बस्तवासियों को गहरे मंथन करने और निर्णय लेने की आवश्यकता है। आप सभी युवाओं से अनुरोध है कि इस नक्सल विचारधारा को समाप्त करने की दिशा में सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से लोगों को जागरूक करें ताकि बस्तर नक्सल मुक्त हवा में शांति और सुकून की साँस ले सके।

छोटेडोंगर में आयोजित समाधान शिविर में लीमेश्वर भोयर को मिला मछली जाल

- मुख्यमंत्री साय को किया धन्यवाद ज्ञापित

नारायणपुर 19 मई (दण्डकारण्य समाचार) सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत जिले के ग्राम छोटेडोंगर में गत दिवस को आयोजित समाधान शिविर में बड़ागांव निवासी लीमेश्वर भोयर को एक मछली जाल प्रदाय किया गया। लीमेश्वर ने शासकीय योजना से लाभान्वित होने पर खुशी जाहिर की। लीमेश्वर ने बताया कि उनके पास आधा एकड़ एक तालाब है जिसमें वे मछली का पालन करते हैं। तालाब में रोहू कतला तिलापिया ग्रास कार्प कोमल कार जैसी मछलियों का पालन करते हैं इससे उनकी अच्छी आमदनी हो जाती है। समाधान शिविर में मछली जाल करने पर उनके चेहरे पर खुशियां झलक रही थी। लीमेश्वर द्वारा शिविर में मछली पालन हेतु ऋणा के लिए भी आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

मछली पालन हेतु 4 लाख रूपये का प्रकरण तैयार कर 15 मई को जिला सहकारी बैंक छोटेडोंगर भेजा गया है जिसका शीघ्र स्वीकृति दिया जाएगा। लाभान्वित होने पर लीमेश्वर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद ज्ञापित किया। उल्लेखनीय है कि मछली पालन विभाग के राज्य पोषित योजनाएं अंतर्गत नाव जाल या जाल क्रय की सुविधा दी जाती है। तालाबों जलाशयों अथवा नदियों में मत्स्ययाखेट करने वाले सभी वर्ग के सक्रिय मछुआरों को नाव जाल उपकरण क्रय करने हेतु प्रति मछुआरा 10 हजार रूपए की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही मछली पालकों के लिए फ़िरलिंग क्रय कर संचयन पर सहायताएं फुटकर मत्स्य विक्रय के लिए सहायता मत्स्य बीज संवर्धन तालाब सुधार एवं इनपुट्स मत्स्य बीज के लिए 30 हजार रूपए की आर्थिक सहायत उपलब्ध कराई जाती है। योजना के अंतर्गत झींगा पालन एवं अलंकारिक के लिए अनुसूचित



जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालकों को तीन वर्षों में आर्थिक सहायता दी जाती है। मत्स्य विभाग द्वारा पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों को मछली पालन के लिए उपकरण एवं अन्य प्रयोजनों तथा तालाब पट्टा मत्स्य बीज नाव जाल क्रय के लिए पात्रतानुसार 3 लाख रूपए प्रति सहकारी समिति को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसी तरह मत्स्य पालन विभाग द्वारा मछुआ समितियों को रोजगार में वृद्धि करने के लिए शासकीय योजनाओं से आर्थिक सहायता एवं अनुदान दिया जाता है।